Q.1) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या तीस होगी।
2. चौथे न्यायाधीशों के मामले (Fourth Judges Case) में सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार निर्णय दिया कि भारत के मुख्य न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों से मिलकर गठित कॉलेजियम से परामर्श करना चाहिए।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) दोनों 1 और 2
d) न तो 1 और न ही 2

Q.1) Solution (c)

भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या तैतीस (33) होगी।

इसलिए कथन 1 गलत है।

तीसरे न्यायाधीशों के मामले (Third Judges Case) में उच्चतम न्यायालय ने पहली बार निर्णय सुनाया कि भारत के मुख्य न्यायाधीश को कोलेजियम से परामर्श करना चाहिए जिसमें उच्चतम न्यायालय के चार वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होंगे। (दूसरे न्यायाधीशों के मामले (second judges case) में यह केवल दो वरिष्ठतम न्यायाधीश था)

इसलिए कथन 2 गलत है।

Q.2) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. 84 वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाता है।
2. सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश 5 वर्ष तक पद पर रह सकते हैं या जब तक वह पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेते हैं, जो भी पहले हो।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) दोनों 1 और 2
d) न तो 1 और न ही 2

Q.2) Solution (d)

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) की नियुक्ति की निश्चित प्रक्रिया पर संविधान मौन है। वरिष्ठतम न्यायाधीश को CJI के रूप में नियुक्त करना एक कन्वेंशन है जिसे 1993 में सर्वोच्च न्यायालय ने भी स्वीकार किया है

इसलिए कथन 1 गलत है।

सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश तब तक पद धारण कर सकता है जब तक वह पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता।

इसलिए कथन 2 गलत है।

Q.3) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. कोई भी व्यक्ति जिसने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदभार संभाला है, भारत के भीतर उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय को छोड़कर, वह किसी भी न्यायालय में कोई पदभार ग्रहण नहीं करेगा।

2. जब भारत के मुख्य न्यायाधीश अपने कार्यालय के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ होते हैं, तो कार्यालय के कर्तव्यों का पालन सर्वोच्च न्यायालय के अगले वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा किया जाएगा।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) दोनों 1 और 2
d) न तो 1 और न ही 2

Q.3) Solution (d)

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पद पर आसीन कोई भी व्यक्ति भारतीय क्षेत्र के किसी भी न्यायालय में पदभार ग्रहण नहीं करेगा।

इसलिए कथन 1 गलत है।

जब भारत के मुख्य न्यायाधीश का कार्यालय रिक्त होता है या जब मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थिति के कारण या अन्यथा, अपने कार्यालय के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ होते हैं, तो कार्यालय के कर्तव्यों का निर्वहन किसी अन्य न्यायाधीशों में से एक द्वारा किया जाएगा, जिसे राष्ट्रपति न्यायालय में इस उद्देश्य के लिए नियुक्त कर सकता है।

इसलिए कथन 2 गलत है।

Q.4) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. जब सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी सत्र को आयोजित करने या जारी रखने के लिए स्थायी न्यायाधीशों के कोरम की कमी होती है, तो राष्ट्रपति एक अस्थायी अवधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीश के रूप में एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नामित करता है।
2. राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से भारत का मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश से अस्थायी अवधि के लिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का अनुरोध कर सकता है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) दोनों 1 और 2
d) न तो 1 और न ही 2

Q.4) Solution (a)

जब सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी सत्र को आयोजित करने या जारी रखने के लिए स्थायी न्यायाधीशों के कोरम की कमी होती है, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश एक अस्थायी अवधि के लिए उच्चतम न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीश के रूप में एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नामित कर सकते हैं। वह संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद ही ऐसा कर सकता है

इसलिए कथन 1 गलत है।

राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से भारत का मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश से अस्थायी अवधि के लिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का अनुरोध कर सकता है।

इसलिए कथन 2 सही है।

Q.5) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. संविधान यह कहता है कि कानून द्वारा संसद (राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति के साथ) अन्य स्थान या स्थानों को सर्वोच्च न्यायालय की सीट के रूप में नियुक्त कर सकती है।

2. भारतीय क्षेत्र में, आपराधिक मामलों के केस में उच्च न्यायालय के किसी भी निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश के लिए सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की जा सकती है, लेकिन सिविल मामलों में नहीं।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) दोनों 1 और 2
d) न तो 1 और न ही 2

Q.5) Solution (d)

सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में या ऐसे अन्य स्थान या स्थानों पर बैठेगा, जिसे भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ समय-समय पर नियुक्ति कर सकते हैं।

इसलिए कथन 1 गलत है।

भारतीय क्षेत्र में उच्च न्यायालय के किसी भी निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश, चाहे वह एक नागरिक, अपराधी या अन्य कार्यवाही में हो, के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है।

इसलिए कथन 2 गलत है।

Q.6) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राज्य के विषयों पर संसद द्वारा बनाए गए कानून आपातकाल की समाप्ति के छह महीने बाद निष्क्रिय हो जाते हैं।
2. राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किसी राज्य की विधायिका की विधायी शक्ति निलंबित नहीं की जाती है, यह संसद की अतिव्यापी शक्ति (overriding power) के अधीन हो जाती है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) दोनों 1 और 2
d) न तो 1 और न ही 2

Q.6) Solution (c)

राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राज्य के विषयों पर संसद द्वारा बनाए गए कानून आपातकाल समाप्ति के छह महीने बाद निष्क्रिय हो जाते हैं।

इसलिए कथन 1 सही है।

किसी राज्य की विधायिका की विधायी शक्ति निलंबित नहीं होती है, यह संसद की अतिव्यापी शक्ति के अधीन हो जाती है। इस प्रकार, केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का सामान्य वितरण निलंबित होता है, हालांकि राज्य विधानसभाएं निलंबित नहीं होती हैं।

इसलिए कथन 2 सही है।

Q.7) अनुच्छेद 358 और 359 मौलिक अधिकारों पर राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव का वर्णन करता है। इस संबंध में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है?

a) अनुच्छेद 358 केवल अनुच्छेद 19 द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों के निलंबन से संबंधित है।
b) अनुच्छेद 358 आपातकाल घोषित होते ही राष्ट्रपति को अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकारों को निलंबित करने का अधिकार देता है।
c) राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान की गई विधायी और कार्यकारी कार्रवाइयों को आपातकाल समाप्ति के बाद भी चुनौती नहीं दी जा सकती है।

d) अनुच्छेद 359 बाह्य आपातकाल और आंतरिक आपातकाल दोनों के मामले में संचालित होता है

Q.7) Solution (b)

अनुच्छेद 358 अनुच्छेद 19 द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों के निलंबन से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 359 अन्य मौलिक अधिकारों के निलंबन (अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा गारंटीकृत अधिकारों को छोड़कर) से संबंधित है।

इसलिए कथन 1 सही है।

आपातकाल घोषित होते ही अनुच्छेद 358 स्वचालित रूप से अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकारों को निलंबित कर देता है। दूसरी ओर, अनुच्छेद 359 किसी भी मौलिक अधिकार को स्वचालित रूप से निलंबित नहीं करता है। यह केवल राष्ट्रपति को निर्दिष्ट मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित करने का अधिकार देता है।

इसलिए कथन 2 गलत है।

आपातकाल के समाप्त होने के बाद भी, आपातकाल के दौरान की गयी कार्यवाहियों के विरुद्ध कोई भी उपचार उपलब्ध नहीं होता है। इसका मतलब यह है कि आपातकाल के दौरान की गई विधायी और कार्यकारी कार्रवाइयों को आपातकाल के बाद भी चुनौती नहीं दी जा सकती है।

इसलिए कथन 3 सही है।

अनुच्छेद 358 केवल बाह्य आपातकाल के मामले में संचालित होता है, जबकि अनुच्छेद 359 बाह्य आपातकाल और आंतरिक आपातकाल दोनों के मामले में संचालित होता है।

इसलिए कथन 4 सही है।

Q.8) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश राष्ट्रपति को पत्र लिखकर अपने कार्यालय से इस्तीफ़ा दे सकते हैं।
2. सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करके, संसद द्वारा पारित किसी भी असंवैधानिक संशोधनों से संविधान की रक्षा करता है।

उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) दोनों 1 और 2
d) न तो 1 और न ही 2

Q.8) Solution (c)

सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश राष्ट्रपति को पत्र लिखकर अपने कार्यालय से इस्तीफ़ा दे सकते हैं।

सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करके, संसद द्वारा पारित किसी भी असंवैधानिक संशोधनों से संविधान की रक्षा करता है।

Q.9) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. उच्च न्यायालय किसी भी व्यक्ति, प्राधिकरण और सरकार को अपने प्रादेशिक क्षेत्राधिकार (territorial jurisdiction) में ही रिट जारी कर सकता है।
2. अनुच्छेद 32 के तहत उच्च न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार अनन्य (exclusive) नहीं है लेकिन अनुच्छेद 226 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार के साथ समवर्ती (concurrent) है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है / हैं?

a) केवल 1

b) केवल 2
c) दोनों 1 और 2
d) न तो 1 और न ही 2

Q.9) Solution (c)

उच्च न्यायालय किसी भी व्यक्ति, प्राधिकरण और सरकार को न केवल अपने प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के भीतर, बल्कि अपने प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के बाहर भी रिट जारी कर सकता है, यदि कार्रवाई का कारण उसके प्रादेशिक अधिकार क्षेत्र में आता है।

इसलिए कथन 1 गलत है।

उच्च न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार (अनुच्छेद 226 के तहत) सर्वोच्च न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार (अनुच्छेद 32 के तहत) के साथ अनन्य नहीं बल्कि समवर्ती है। इसका अर्थ है कि, जब किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो पीड़ित पक्ष के पास सीधे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में जाने का विकल्प होता है।

इसलिए कथन 2 गलत है।

Q.10) निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वायत्तता की रक्षा करता है?

1. भारत के राष्ट्रपति संसद के परामर्श से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं।
2. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत अपने पद पर आसीन रहते हैं।
3. न्यायाधीशों का वेतन भारत के समेकित कोष पर भारित किया जाता है, जिसके लिए विधायिका को मतदान नहीं करना पड़ता है।

नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें:

a) केवल 1
b) केवल 1 और 2
c) केवल 3
d) 1, 2 और 3

Q.10) Solution (c)

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय, भारत के राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करना होता है।

इसलिए कथन 1 गलत है।

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति द्वारा पद से केवल संविधान में वर्णित उस तरीके से और आधार पर हटाया जा सकता है। इसका अर्थ यह है कि वे राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत अपने पद पर आसीन नहीं रहते हैं, हालांकि वे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं।

इसलिए कथन 2 गलत है।

न्यायाधीशों और कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन के साथ-साथ सर्वोच्च न्यायालय के सभी प्रशासनिक खर्चों को भारत के समेकित कोष पर भारित किया गया है। इस प्रकार, वे संसद द्वारा गैर-मतदान योग्य हैं।

इसलिए कथन 3 सही है।

Q.1) नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा / से विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (FCRA) के संबंध में सही है?

1. यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कार्यान्वित, वित्तीय विधान (financial legislation) से संबंधित कानून है।
2. अधिनियम के तहत, विदेशों से धन प्राप्त करने वाले गैर सरकारी संगठनों को प्रत्येक पांच वर्ष में स्वयं को पंजीकृत करने की आवश्यकता होती है।

सही उत्तर चुनें:

a) केवल 1
b) केवल 2
c) दोनों 1 और 2
d) न तो 1 और न ही 2

Q.1) Solution (b)

विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (FCRA)

- यह विदेशी अंशदान (विशेषकर मौद्रिक दान) को विनियमित करने के लिए संसद द्वारा अधिनियमित कानून है
- एफसीआरए अधिनियम 2010 के अनुसार, विदेशी धन प्राप्त करने के लिए सभी गैर सरकारी संगठनों को अधिनियम के तहत पंजीकृत होना आवश्यक है।
- अधिनियम के तहत, संगठनों को प्रत्येक पांच वर्ष में स्वयं को पंजीकृत करने की आवश्यकता होती है।
- चूंकि अधिनियम, वित्तीय कानून से संबंधित कानून होने के बावजूद, आंतरिक सुरक्षा कानून है, यह गृह मंत्रालय के दायरे में आता है, न कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के।

Source: https://www.thehindu.com/todays-paper/three-ngos-linked-to-congress-under-home-ministry-scanner/article32026705.ece

Q.2) प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) मिशन के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह योजना वर्ष 2022 तक शहरी क्षेत्रों में सभी को आवास प्रदान करने के लिए है।
2. इसका उद्देश्य प्रत्येक परिवार को पानी के कनेक्शन, शौचालय की सुविधा, 24 * 7 बिजली की आपूर्ति और पहुंच के साथ एक पक्का घर प्रदान करना है।
3. PMAY (U) ने परिवार की महिला मुखिया के लिए इस मिशन के तहत घर का मालिक या सह-मालिक होने का अनिवार्य प्रावधान किया है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

a) 1 और 3
b) केवल 3
c) 1 और 2
d) 1, 2 और 3

Q.2) Solution (c)

शहरी क्षेत्रों में सभी के लिए आवास सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2015-2022 के दौरान कार्यान्वयन के लिए 25 जून 2015 को आरंभ की गई थी।

यह योजना वर्ष 2022 तक शहरी क्षेत्रों में सभी को आवास प्रदान करने के लिए है।

मिशन राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) और केंद्रीय नोडल एजेंसियों (CNAs) के माध्यम से कार्यान्वयन एजेंसियों को केंद्रीय पात्रता प्रदान करता है, जो सभी लगभग 1.12 करोड़ पात्र परिवारों / लाभार्थियों को घरों की वैध मांग के सापेक्ष आवास प्रदान करते हैं।

PMAY (U) के दिशानिर्देशों के अनुसार, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए एक घर का आकार 30 वर्ग मीटर तक हो सकता है। हालांकि राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों में मंत्रालय के परामर्श और अनुमोदन में घरों के आकार को बढ़ाने के लिए लचीलापन है।

पूर्ववर्ती योजनाओं के विपरीत EWS और LIG की महिलाओं के सशक्तीकरण की दिशा में सरकार के इस प्रयास को जारी रखते हुए, PMAY (U) ने परिवार की महिला मुखिया के लिए इस मिशन के तहत घर की मालिक या सह-मालिक होने का एक अनिवार्य प्रावधान किया है।

इस योजना को अन्य योजनाओं के साथ अभिसरित (converged) किया गया है ताकि घरों में शौचालय, सहज योजना बिजली कनेक्शन, उज्ज्वला योजना एलपीजी गैस कनेक्शन, पीने के पानी तक पहुंच और जन धन बैंकिंग की सुविधा, आदि सुनिश्चित हो सके।

Source: **https://www.thehindu.com/news/national/cabinet-nod-for-development-of-affordable-rental-housing-complexes-for-urban-migrants-poor/article32022523.ece**

https://pmay-urban.gov.in/about

Q.3) संयुक्त राष्ट्र के छह मुख्य अंगों में से कौन से अंग हैं?

1. अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (International Court of Justice)
2. अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय (International Criminal Court)
3. आर्थिक और सामाजिक परिषद (Economic and Social Council)
4. न्यास परिषद (Trusteeship Council)

सही उत्तर चुनें:

a) 1 और 2
b) 3 और 4
c) 1, 3 और 4
d) 1, 2, 3 और 4

Q.3) Solution (c)

संयुक्त राष्ट्र के छह मुख्य अंग हैं:

- **महासभा (General Assembly):** संयुक्त राष्ट्र का मुख्य विचार-विमर्श, नीति-निर्धारण और प्रतिनिधि अंग
- **सुरक्षा परिषद (Security Council):** अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी
- **आर्थिक और सामाजिक परिषद (Economic and Social Council):** समन्वय, नीति समीक्षा, नीति संवाद तथा आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय मुद्दों पर सिफारिशों के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहमत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए प्रमुख निकाय
- **न्यास परिषद (Trusteeship Council):** 11 ट्रस्ट क्षेत्रों के लिए अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षण प्रदान करता है जो सात सदस्य राज्यों के प्रशासन के तहत रखा गया था। हालांकि, 1 नवंबर 1994 को इसके संचालन को निलंबित कर दिया।
- **अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (International Court of Justice):** संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग
- **सचिवालय (Secretariat):** महासभा और संगठन के अन्य प्रमुख अंगों द्वारा अनिवार्य रूप से संयुक्त राष्ट्र के दिन-प्रतिदिन के कार्य को पूरा करता है

Q.4) संयुक्त राष्ट्र के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय संयुक्त राष्ट्र के दो विवाद समाधान तंत्र हैं।
2. संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य राष्ट्र, यूनेस्को के भी सदस्य हैं।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) दोनों 1 और 2
d) न तो 1 और न ही 2

Q.4) Solution (d)

नीदरलैंड के हेग में स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ), संयुक्त राष्ट्र का प्राथमिक न्यायिक अंग है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का प्राथमिक उद्देश्य राज्यों के बीच विवादों का समाधान करना है।

यूनेस्को के तीन सदस्य राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश नहीं हैं: कुक आइलैंड्स, नीयू (Niue), और फिलिस्तीन (फिलिस्तीन संयुक्त राष्ट्र महासभा का एक गैर-सदस्यीय पर्यवेक्षक राज्य है जो 29 नवंबर 2012 से है), जबकि एक संयुक्त राष्ट्र सदस्य राज्य (लिचेंस्टीन) यूनेस्को का सदस्य नहीं है।

अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) एक स्वतंत्र न्यायिक निकाय है जिसके पास जनसंहार, मानवता के खिलाफ अपराध और युद्ध अपराधों के आरोप वाले व्यक्तियों पर जनादेश है। यह नीदरलैंड के हेग में बैठता है।

न्यायालय की स्थापना रोम संविधि (Rome Statute) द्वारा की गई थी। संयुक्त राष्ट्र के भीतर इस संधि पर बातचीत की गई थी; हालाँकि, इसे संयुक्त राष्ट्र से अलग एक स्वतंत्र न्यायिक निकाय बनाया गया।

Q.5) अफॉर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स (Affordable Rental Housing Complexes -ARHCs) के बारे में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया था?

a) आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने ARHCs का शुभारंभ किया है।
b) ARHCs प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-U) के अंतर्गत एक उप-योजना है।
c) ARHCs के लिए लाभार्थी EWS/ LIG श्रेणियों से शहरी प्रवासी / गरीब होंगे।
d) इनमें से कोई भी नहीं

Q.5) Solution (d)

प्रवासियों कामगारों / शहरी गरीबों के लिए अफॉर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स (ARHCs)

- आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने **अफॉर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स/ किफायती किराया आवासीय परिसर (ARHCs)** की शुरुआत की है, जो प्रधानमंत्री आवास योजना- शहरी (PMAY-U) के तहत एक उप-योजना है।
- यह औद्योगिक क्षेत्र के साथ-साथ गैर-औपचारिक शहरी अर्थव्यवस्था में शहरी प्रवासियों / गरीबों को रहने की सुगमता प्रदान करेगा तथा उन्हें अपने कार्यस्थल के करीब गरिमापूर्ण किफायती किराये के आवास की सुविधा प्राप्त होगी।

ARHC योजना दो मॉडलों के माध्यम से कार्यान्वित की जाएगी:

- मौजूदा सरकारी वित्त पोषित खाली घरों को सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से या सार्वजनिक एजेंसियों द्वारा ARHCs में परिवर्तित करना
- सार्वजनिक / निजी संस्थाओं द्वारा अपनी खाली पड़ी भूमि पर ARHCs का निर्माण, संचालन और रखरखाव

ARHCs के लिए लाभार्थी EWS/ LIG श्रेणियों से शहरी प्रवासी / गरीब होंगे। ARHCs सभी सामान्य सुविधाओं सहित एकल बेडरूम आवासीय इकाइयों और 4/6 बिस्तरों के शयनगृह (Dormitory) का मिश्रण होगा, जो विशेष रूप से 25 वर्षों की न्यूनतम अवधि के लिए किराये के आवास के लिए उपयोग किया जाएगा।

Source: https://pmay-urban.gov.in/arhc-about

https://www.thehindu.com/news/national/cabinet-nod-for-development-of-affordable-rental-housing-complexes-for-urban-migrants-poor/article32022523.ece